(च) क्या विधवा के स्वर्गीय पति के नाम पर निकाली गई राशि को अब विधवा के परिवार के खाते में जमा किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Implementation of transfer orders regarding bank staff

346. DR. BAPU KALDATE:

SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of status-quo orders relating to transfer of staff received by the Branches of Associate Banks of the State Bank of India situated at Chandni Chowk, Delhi, issued by the Assistant Labour Commissioner (Central), Dalhousie Road, New Delhi during 1st June, 1985 to 15th June, 1985 with details, bankwise and branch-wise;

(b) whether these status-quo orders were implemented; if not, the reasons therefor stating the action taken by Government against Bank Management for non-compliance the status-quo orders;

(c) whether it is a fact that transfer orders were effected even after receiving the status-quo orders issued by the Assistant Labour Commissioner; and

(d) if so, what action has been taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

हरिजनों पर अत्याचार

347. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिजनों एवं आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) वर्षवार एवं राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनायें हुई हैं तथा इन घटनाओं में मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(घ) हरिजनों तथा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	अनुसूचित जातियों	अनुसूचित जनजातियों
	के विरुद्ध	अपराध
1988	15,207	3,364
1989	15,799	3,623
1990	16,810	3,572

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार करने के कारण अनेक रहे हैं, जैसे-भूमि विवाद, कानूनी न्यूनतम मजदूरी की मांग, बंधवा मजदूर अथवा जबरन मजदूरी प्रथा प्रतिरोध, अस्पृश्यता की प्रथा का विरोध, शिक्षा के माध्यम से उत्पन्न जागरूकता के कारण समान अधिकारों के दावे, अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा के प्रयास आदि ।

(ग) सूचना जहां तक उपलब्ध है, अनुसूचित जातियों के संबंध में और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अपेक्षित सूचना पृथक-पृथक अनुपत्रों में दी गई है। (देखिए परिशिष्ट 160 अनुपत्र संख्या 18 और 19)।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार किए जाने को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पारित कर दिया गया है। इस अधिनियम में कठोर दन्डों की व्यवस्था है। अधिनियम के अंतर्गत अत्याचारों के मामलों के शीघ्र परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इस अधिनियम में अत्याचारों के शिकार लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था है। भारत सरकार नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दोनों के कार्यान्वियन का खर्च राज्य सरकारों के साथ बराबरी के आधार 50 : 50 पर वहन करती है। सरकार द्वारा एहतियाती निवारक, दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपायों को शामिल करते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने हेतु राज्य सरकारों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

Removal of bank from Joint Consultative Machinery for Kendriya Vidyalaya Sangathan

348. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1161 given in the Rajya Sabha on the 30th July, 1991 and state the details of efforts, if any, made by the Kendriya Vidyalaya Sangathan to overcome the disagreement regarding the number of representatives of different associations on the Council under the J.C.M. scheme and the result achieved?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Since the objections were raised by the teaching and non-teaching associations on the distributions of seats on the staff side of Joint Consultative Machinery, the matter was referred to Ministry of Law & Justice and the Legal Adviser to Kendriya Vidyalaya Sangathan. There was a difference of opinion in advice in procedure in convening the meeting of J.C.M. Hence, a second advice has been sought from the Ministry of Law & Justice. Simultaneously, the matter of verification of membership of Rashtriya Kendriya Vidyalaya Adhyapak Sangh (two factions) has been referred to Department of Personnel on the advice of the Chief Labour Commissioner, Ministry of Labour.

CGHS dispensary at Laxmi Nagar

349. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1373 given in the Rajya Sabha on the 30th July, 1991 and state:

(a) when the CPWD was asked to construct the CGHS building in Laxmi Nagar;

(b) what progress has been made in its construction;

(c) if no, progress has been made, what are the reasons therefor;

(d) whether his Ministry has the responsibility to see that CGHS building comes up without any delay;

(e) if so, what steps are being taken from time to time to ensure timely construction of the building;

(f) since the cost has gone up considerably, whether any responsibility has been fixed on those who have delayed the project; and

(g) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFORE (SMT. D. K. THARADEVI SIDDHARTHA): (a) to (c) Possession of a plot of land measuring 0.41 acre at